

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: २ जून, २००६  
विषय:-केन्द्रज हैल्थकेयर लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग हेतु तहसील रुड़की के ग्राम रायपुर में कुल ०.६४८० है० भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५९८/भूमि व्यवस्था-भूमि क्य -२००५ दिनांक २८-०४-२००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रज हैल्थकेयर लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम रायपुर में कुल ०.६४८० है० भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिवर्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

१- केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

२- केता वैक या वित्तीय संरथाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी गृणी वन्धु या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस गृणी का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-१६७ के परिणाम लागू होंगे।

- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुरूपित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7— औद्योगिक आरथान के नियोजन के अनुरूप उद्योग स्थापित किया जायेगा।
- 8— सर्वज्ञ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाइलॉज के आधार पर फैक्टी का निर्माण किया जायेगा।
- 9— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलब्धाल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तदनिमंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।  
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।  
3— सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।  
4— श्री कृष्ण कुमार भगोरिया, डायरेक्टर, कैन्ट्ज हैल्थकेयर लिलो, 12-गांधी स्कॉर, मलका गंज, नई दिल्ली।  
5— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।  
6— गार्ड फाईल।

आश्चित्ता से,

(सोहन लाल)  
अपर सचिव।